

part of the Sixth Plan are as follows:—

(Rs. in crores)

| Name of Port    | Allocation for 1982-83 | Estimated outlay for remaining part of Sixth Plan 1983-84 & 1984-85 |
|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Calcutta/Haldia | 13.26                  | 48.33                                                               |
| Paradip         | 9.54                   | 32.17                                                               |
| Visakhapatnam   | 10.75                  | 44.49                                                               |
| Madras          | 17.59                  | 35.48                                                               |
| Tuticorin       | 7.37                   | 7.66                                                                |
| <b>TOTAL</b>    | <b>58.51</b>           | <b>168.13</b>                                                       |

The Union Ministry of Agriculture is responsible for development of fishing harbours. According to information furnished by that Ministry, there are two schemes, namely, Central Sector Schemes for construction of major ports and Centrally Sponsored Schemes for minor ports. Under these schemes major harbours at Roychowk (West Bengal) and at Visakhapatnam (stage-I) and minor harbours at Tuticorin, Dhamra and Port Blair have already been completed on the East Coast.

• A major fishing harbour at Madras and minor fishing harbours at Visakhapatnam (stage-II), Digha, Kakinada, Nizampatnam, Bhavnepadu, Volinokkam and Chinnamuttom on the East Coast have already been sanctioned and are under construction.

A provision of Rs. 36 crores has been provided for the development of fishing harbours in the country in the Sixth Plan out of which a sizeable amount will be utilised on the sanctioned projects which are yet to be completed.

As regards the minor ports, as per the decision of the National Development Council, responsibility for development of these ports vests with the State Governments concerned.

### इलाहाबाद में कर्जन पुल के समानान्तर एक पुल का निर्माण

494. श्री रामपूजन पटेल : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद में कर्जन पुल के भारी यातायात के लिए बन्द किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों से आने वाली बसों तथा ट्रकों को लगभग 30 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार लोगों को हो रही कठिनाई को दूर करने के लिए इस पुल के समानान्तर एक और पुल बनाने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में हुई प्रगति का व्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) कर्जन पुल राज्य सड़क पर है। यह पुल जब बना था तब भी यह राज्य सड़क पर ही था। इसलिए यह उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। भारत सरकार जो राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए ही उत्तरदायी है, राष्ट्रीय राजमार्ग के यातायात की सुविधा के लिए पहले से ही कीटोनमेंट क्षेत्र के निकट एक नया चार लेनों के पुल का निर्माण कर चुकी है।